निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए दृष्टिकोण*

यह आलेख परियोजना प्रस्तावों द्वारा इंगित निवेश चरणबद्ध योजना के अनुसार निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश प्रयोजन से संबंधित आंकड़ों के आधार पर भारत में निजी निवेश गतिविधि के लिए निकट-अवधि के दृष्टिकोण की जांच करता है। 2020-21 में कोविड के प्रभाव को दर्शाते हुए, स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई और पहले से ही प्रक्रियाधीन परियोजनाओं पर धीमी प्रगति हुई। निवेश के दृष्टिकोण से प्रक्रियाधीन परियोजनाओं से संबंधित 2021-22 के लिए चरणबद्ध योजनाओं पर डेटा निकट-अवधि के जोखिमों को बनाए रखने की ओर इशारा करता है।

भूमिका

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अर्थव्यवस्था में निवेश के वातावरण का एक प्रमुख संकेतक है। निजी निवेश उच्च वृद्धि को गति प्रदान कर सकता है और उसे रोक सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, वृद्धि की संभावनाओं का आकलन करने के लिए निजी निवेश दृष्टिकोण का आंकलन महत्वपूर्ण है। हालांकि, निवेश संबंधित विवरण रखने वाली कंपनियों के वार्षिक लेखे काफी समय अंतराल के बाद प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता अल्पकालिक दूरंदेशी विश्लेषण तक सीमित हो जाती है।

साहित्यिक समीक्षा से पता चलता है कि देश अक्सर परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं और निवेश प्रयोजन पर जानकारी उत्पन्न करने के लिए सर्वेक्षण आधारित विधियों का उपयोग करते हैं। इस तरह के सर्वेक्षणों के परिणाम वर्तमान निवेश माहौल और निवेश के इरादे दोनों के आंकलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनकी लघु से मध्यम अवधि में अमल में आने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से निजी निवेश के आंकलन और पूर्वानुमान/ तात्कालिक अनुमान के लिए भारत में भी सर्वेक्षण करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

रिज़र्व बैंक लंबे समय से उन परियोजनाओं के माध्यम से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की पूंजीगत व्यय योजनाओं पर नज़र रखता रहा है, जिन्हें रंगराजन (1970)[1] द्वारा कैपेक्स के समय पर चरणबद्ध तरीके से अपनाई गई कार्यप्रणाली पर आधारित निवेश पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इस तरह के आलेख शुरूआत में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में और बाद में 1989 से बुलेटिन में प्रकाशित हुए थे।

निवेश के प्रयोजन पर डेटा का प्राथमिक स्रोत कैपेक्स परियोजनाओं के पित्तपोषक हैं, *जैसे* बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्था (एफआई)[2] के साथ-साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)[3], विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी), रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड (आरडीबी) और एक वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और अधिकार निर्गम।

इसके अतिरिक्त, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के कैपेक्स डेटाबेस से पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर विस्तृत स्तर का डेटा, जो उनकी प्रगति से, घोषणा से लेकर पूरा होने तक (पूरी हुई परियोजनाओं के लिए), समाप्ति (परित्यक्त/ स्थगित परियोजनाओं के लिए) और मध्यवर्ती घटनाओं (लाइव परियोजनाओं के लिए) से संबंधित है, का उपयोग परियोजनाओं के जीवन चक्र का आंकलन करने के लिए भी किया गया है (बॉक्स 1)।

---

* इस आलेख को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग में राजेंद्र एन चव्हाण, प्रोनिता पी सैकिया और आर के सिन्हा द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पिछला अध्ययन "वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश: सुधार के आसार" भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के फरवरी 2020 अंक में प्रकाशित हुआ था।

[1] यह कार्य-प्रणाली 19 दिसंबर, 1970 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडबल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा लिखित आलेख "कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान" में प्रकाशित हुआ था।

[2] सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक, और वित्तीय संस्थाएं जो परियोजना के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अर्थात्, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) शामिल हैं। भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम)।

[3] ईसीबी में रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्ड (आरडीबी) शामिल हैं।

बॉक्स 1: पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का जीवन चक्र

पूंजीगत व्यय परियोजना का जीवन चक्र[4] आमतौर पर इसकी घोषणा के साथ शुरू होता है और उसके बाद विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, जैसे कि विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करना, वित्तीय पूर्णता प्राप्त करना, ऋण की मंजूरी, कार्यान्वयन की शुरुआत *आदि*। इस चक्र की परिणति या तो सफलता में हो सकती है, अर्थात् परियोजना का पूर्ण होना, या एक असफल घटना के रूप में इसके पूरा होने से पहले समाप्ति[5] के माध्यम से। ऐसी परियोजनाएं, जो समाप्त नहीं हुई हैं (सभी चरणों के पूरा होने के माध्यम से), को लाइव प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है। कुछ परियोजनाएँ जो घोषणा और पूर्ण होने के बीच कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, उन्हें "अवरुद्ध" परियोजनाओं की संज्ञा दी जाती है।

घोषणाएं और उनकी पूर्णता

2020-21 के दौरान पूर्ण की गई निजी परियोजनाओं की संख्या में काफी गिरावट आयी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह केवल 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के वर्ष के दौरान मामूली गिरावट आयी थी, और बाद में कुछ अस्थिरता के साथ 2011-12 तक बढ़ी। इसमें 2013-14 से 2018-19 तक लगातार इजाफा हुआ और 2019-20 में गिरावट आई जो कि महामारी-पूर्व प्रचलित मंद दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह 2020-21 में महामारी की गंभीरता को दर्शाता है। नई घोषणाओं की संख्या में भी 2020-21 में और गिरावट आयी। घोषणाओं और पूर्ण होने की घटती प्रवृत्तियां आगे चल रहे पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा को प्रभावित कर सकती हैं (चार्ट 1)।

मासिक डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2020 में केवल आठ निजी परियोजनाएं पूरी हुईं, जिसमें देशव्यापी तालाबंदी देखी गई। इस स्थिति में तब से कुछ सुधार हुआ है, हालांकि ये संख्या सामान्य वर्ष की औसत मासिक संख्या से काफी कम प्रतीत होती है। 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान अपेक्षाकृत अधिक संख्या में निजी परियोजनाओं की घोषणाएं बैकलॉग को कवर कर सकती हैं, *अर्थात* लंबित/ अतिदेय घोषणाओं को, जो तिमाही में प्रबल लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान पूर्ण नहीं हो सकीं (चार्ट 2)।

चार्ट 1: नई घोषणाओं और उनकी पूर्ति की संख्या - वार्षिक

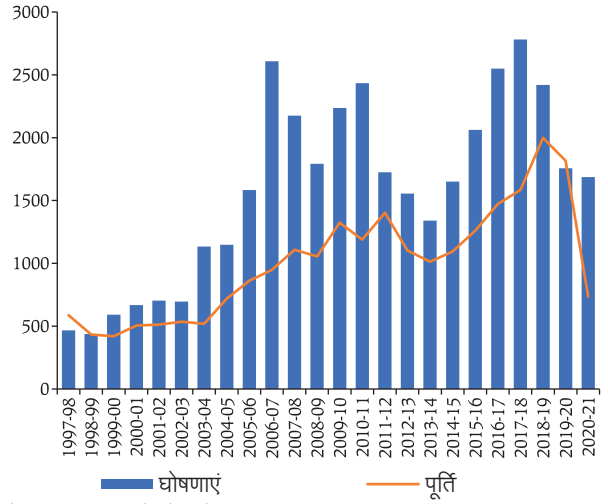

स्रोत: सीएमआईई और लेखकों द्वारा की गई गणना

चार्ट 2: नई घोषणाओं और उनकी पूर्ति की संख्या - मासिक

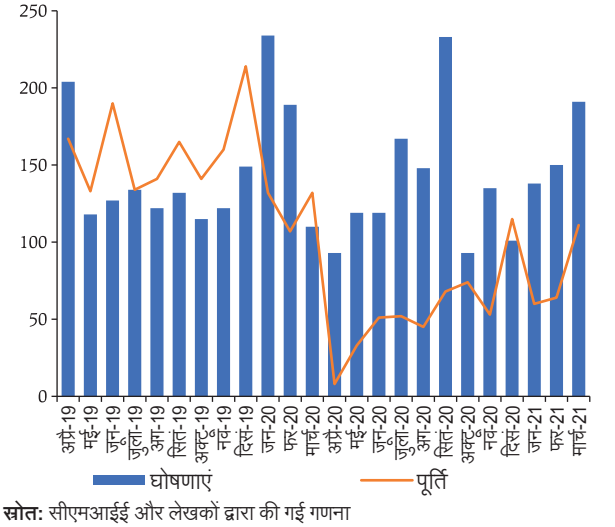

स्रोत: सीएमआईई और लेखकों द्वारा की गई गणना

(जारी...)

[4] एक पूंजीगत व्यय परियोजना के जीवन चक्र से तात्पर्य परियोजना के पूर्ण होने से पहले के विभिन्न चरणों को कवर करने वाले चक्र से है। एक अन्य जीवन चक्र के बारे में सोचा जा सकता है कि परियोजना के पूरा होने/ चालू होने से लेकर उसके ध्वस्त होने या अप्रयुक्त होने से पहले तक चालू रहने तक के चरण को कवर करने के बारे में सोचा जा सकता है।

[5] परियोजनाओं का अंत किसी भी चरण में हो सकता है। सबसे पहली संभावना घोषणा के बाद ही परियोजना का परित्याग है (किसी और चरण में बिना आगे बढ़े)। यह विभिन्न अनुमोदन चरणों (घोषणा के बाद लेकिन कार्यान्वयन की शुरुआत से पहले) के दौरान हो सकता है। की तीसरी संभावना कार्यान्वयन की शुरुआत के बाद है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के कैपेक्स डेटाबेस में बहिर्गमन के इन तीन प्रकारों को क्रमशः "घोषित और परित्यक्त", "शेल्व्ड" और "परित्यक्त" के रूप में परिभाषित किया गया है।

परियोजनाओं को पूर्ण करने का औसत समय

पूर्ण की गई परियोजनाओं का डेटा समूह पुष्टि करता है कि घोषणा की तारीख से किसी परियोजना के पूरा होने का औसत समय उसकी लागत के आकार के साथ धनात्मक संबंध रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि के दौरान और उसके आसपास वृद्धि हुई है और तब से 2014-15 तक उच्च बनी हुई है। 2016-17 के ट्रफ से 2020-21 तक औसत समय फिर से बढ़ गया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोविड जनित वर्ष 2020-21 में परियोजनाओं के पूरा होने के औसत समय में वृद्धि काफी हद तक बड़ी परियोजनाओं के समूह के समय में (लागत आकार ₹1,000 करोड़-₹5,000 करोड़) उसी वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित है। सभी लागत-आकार समूहों में परियोजनाओं के पूर्ण होने की संख्या में गिरावट के अनुरूप, पूर्ण हो गई परियोजनाओं की संख्या 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से कम हो गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में कोई बृहद् परियोजना (लागत आकार ₹5,000 करोड़ और अधिक) नहीं है (चार्ट 3)।

परित्याग/ शेल्व्ड / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय

ऐसी निजी परियोजनाओं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता था और जिसे या तो छोड़ दिया गया था या समाप्त हो गया था, उनका औसत समय वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2017-18 (परित्यक्त परियोजनाओं के लिए) और 2015-16 (शेल्व्ड परियोजनाओं के लिए) के वर्षों में काफी बढ़ गया है। संकलित औसत समय से उनकी संबंधित घोषणाओं के बाद परियोजनाओं को छोड़ने या ठंडे बस्ते में डालने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कई परियोजनाएं, जिन्हें वित्तीय संकट (एक तीव्र वृद्धि की अवधि) से पहले घोषित किया गया था, को छोड़ दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2017-18 के बाद, इन आंकड़ों में कमी आयी है जो यह दर्शाती है कि या तो ऐसी परियोजनाओं की घोषणा में कमी आयी है या निष्पादन योजना में सुधार हुआ है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद परियोजनाओं में विलंब का औसत समय भी धीरे-धीरे बढ़ा, लेकिन 2017-18 से इसमें कमी आयी है (चार्ट 4)।

चार्ट 3: परियोजनाओं को पूर्ण करने का औसत समय

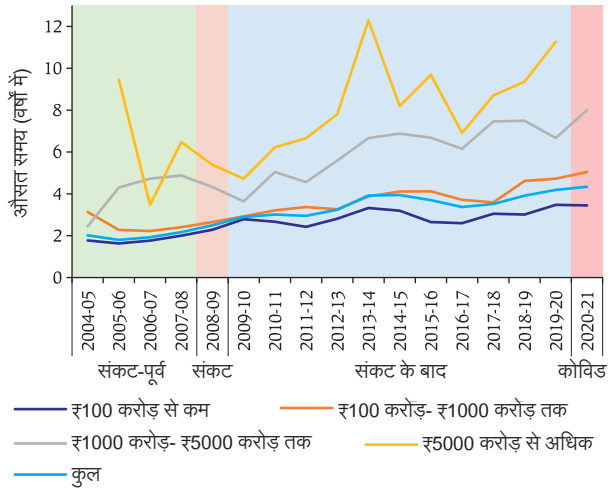

चार्ट 3: परियोजनाओं की पूर्ति/ परित्याग/ शेल्विंग / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय

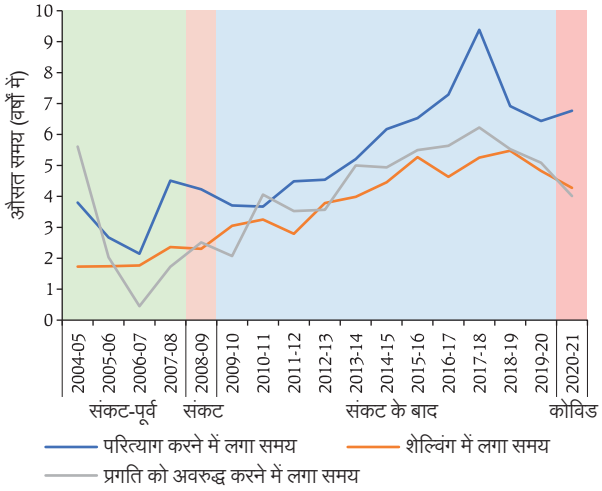

टिप्पणियां:

1. परियोजनाओं की लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाली परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया था।
2. 2019-20 की अवधि भारतीय संदर्भ में केवल कुछ दिनों की कोविद-19 महामारी को कवर करती है। तदनुसार, केवल 2020-21 को महामारी प्रभावित वर्ष के रूप में माना है।
3. पूर्ति/ परित्याग/ शेल्विंग / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय, साधारण औसत पर आधारित है।

स्रोत: सीएमआईई और लेखकों द्वारा की गई गणना

यह आलेख छह खंडों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। खंड II कार्य पद्धति और इसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। खंड III समीक्षा की अवधि के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताओं, उसके वित्त पोषण, और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को संबोधित करता है। खंड IV स्वीकृत/ अनुबंधित ऋणों/ वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। खंड V वर्ष के दौरान किए गए निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VI में अध्ययन का समापन हुआ है।

II. कार्य पद्धति और सीमाएं

पूर्व में दिये गए संकेत के अनुसार, वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट परियोजनाओं के चरणबद्ध विवरण के आधार पर पूंजीगत व्यय के अल्पकालिक (एक वर्ष आगे का) पूर्वानुमान का मार्ग 1970 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा प्रशस्त किया गया था। इस कार्य पद्धति के तहत पूंजीगत व्यय के अनुमान के लिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में परियोजनाओं पर डेटा को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है, जो अन्य स्रोतों जैसे ईसीबी/ एफसीसीबी/ आईपीओ/ एफपीओ/ अधिकार निर्गम के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए जुटाए गए वित्त पर डेटा के पूरक हैं। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन के समय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत *प्रत्याशित* चरणबद्ध योजनाओं के आधार पर, वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय के संभावित स्तर का अनुमान प्राप्त किया जाता है।

इस विश्लेषण में रिज़र्व बैंक के आंतरिक डेटाबेस के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि प्रत्येक परियोजना केवल एक ही बार सूचना समूह में प्रवेश करे, भले ही इसे एक से अधिक स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया हो। जिन परियोजनाओं को उपर्युक्त स्रोतों में से किसी के माध्यम से वित्तपोषित नहीं किया गया है या जिनका आकार ₹10 करोड़ से कम है, वे इसमें शामिल नहीं हैं। 51 प्रतिशत से कम निजी स्वामित्व वाली या ट्रस्टों, केंद्र और राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को भी शामिल नहीं किया गया है।

ये अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपनी *प्रत्याशित* व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट स्थिर निवेश के *वास्तविक* अनुमानों से हट सकते हैं। यह इस संभावना के मद्देनजर है कि कुछ *प्रत्याशित* प्रयोजन उनकी राशि और निवेश के समय के संदर्भ में वास्तविक निवेश में फलित नहीं हो सकते हैं और कुछ परियोजनाएं स्व-वित्तपोषित हो सकती हैं।

III. स्वीकृत/ अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

निवेश का माहौल 2019-20 में सुस्त रहा था, उसे महामारी के मद्देनजर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2020-21 की शुरुआत से ही यह मंद रहा है। नई घोषणाओं की कम संख्या के साथ मौजूदा परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ गई (बॉक्स 1)। 2020-21 के दौरान बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है।

2020-21 की पहली छमाही में नई मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या घटकर 68 पर आ गई, जो 2019-20 की पहली छमाही के दौरान स्वीकृत 137 परियोजनाओं की तुलना में कम है, जो स्पष्ट रूप से कोविड-19 महामारी की भूमिका का संकेत देती है। अधिकांश बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं ने 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 'शून्य' परियोजनाओं की सूचना दी, जो महामारी-जनित अनिश्चितताओं के कारण निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के बहुत ही मंद निवेश वातावरण की ओर इशारा करती है। 2020-21 की दूसरी छमाही में परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए, जिन्हें बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिली, हालांकि इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत के संदर्भ में निवेश का माहौल कमजोर बना रहा।

कुल मिलाकर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने 2020-21 के दौरान निजी कंपनियों के केवल 220 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो हाल के वर्षों में रिकॉर्ड कमी[6] है। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत भी 2020-21 में तेजी से घटकर ₹75,558 करोड़ हो गई, जो 2019-20 में ₹1,75,830 करोड़ थी (अनुबंध: सारणी ए1)।

कुल 344 कंपनियों ने ईसीबी/ एफसीसीबी के माध्यम से ₹40,382 करोड़ की राशि जुटाई और बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से किसी भी तरह के वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, 12 कंपनियों ने किसी भी बैंक वित्त या ईसीबी/ एफसीसीबी का लाभ नहीं उठाया, लेकिन घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से अपनी पूंजीगत जरूरतों के लिए ₹663 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2020-21 के दौरान 576 परियोजनाओं की निवेश योजनाएं कुल ₹1,16,603 करोड़ की थीं, जबकि 2019-20 में 827 परियोजनाओं में कुल 2,71,374 करोड़ रुपये के निवेश प्रयोजन थे (अनुबंध: सारणी ए1-ए4)।

आकार, उद्देश्य, उद्योग और स्थान के अनुसार स्वीकृत/ अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं नीचे वर्णित हैं:

[6] एक वित्तीय वर्ष में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या लगभग 400 (लगभग 100 प्रति तिमाही) रही है, हालांकि गिरावट की प्रवृत्ति (2017-18 में 485, 2018-19 में 409 और 2019-20 में 320) देखी गई है। महामारी-जनित वर्ष 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं की अनंतिम संख्या 220 (पहली छमाही में 68 और दूसरी छमाही में 152) है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को आगे जाकर संशोधित/ निरस्त किया जा सकता है।

(ए) आकार-वार

परियोजनाओं के आकार-वार संवितरण ने कुल परियोजना लागत में इसके संयुक्त हिस्से में कमी के साथ-साथ बृहद् परियोजनाओं (₹ 5,000 करोड़ और अधिक) की संख्या 2019-20 में पांच से कम हो गई और 2020-21 में उल्लेखनीय कमी आयी। इसी तरह, 2020-21 में ₹1000 करोड़-₹5000 करोड़ आकार की बड़ी परियोजनाओं की संख्या 36 (2019-20 में) से घटकर 24 हो गई। हालांकि ऐसी परियोजनाओं की सापेक्ष हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 53.5 प्रतिशत हो गई, जो 2019-20 में 37.4 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं के छोटे समूह में उच्च सापेक्ष उपस्थिति का संकेत देती है। जैसा कि इस आलेख में पहले देखा गया था, परियोजनाओं के जीवन चक्र की घोषणा से लेकर पूर्ण होने तक की अवधि आम तौर पर बड़ी परियोजनाओं के लिए लंबी होती है (बॉक्स 1)। तदनुसार, बृहद्/ बड़ी परियोजनाओं की चरणबद्ध योजना का दीर्घावधि में पूंजीगत व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है (अनुबंध: सारणी ए5)।

(बी) उद्देश्य-वार

परियोजनाओं के उद्देश्य-वार स्वरूप से पता चलता है कि 2020-21 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत में ग्रीन फील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का प्रमुख हिस्सा (94.1 प्रतिशत) था। यह हाल के वर्षों में संरूपी हिस्सेदारी (2018-19 में 76.8 प्रतिशत और 2019-20 में 79.8 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का कुल परियोजना लागत में लगभग 5.9 प्रतिशत का योगदान है (अनुबंध: सारणी ए6)।

(सी) उद्योग-वार

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, और (vi) सड़कें और पुल शामिल हैं। 2019-20 में इनकी हिस्सेदारी 61.5 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 74.3 प्रतिशत हो गई है। इसका श्रेय इसके दो सबसे बड़े घटकों, अर्थात 'बिजली क्षेत्र' और 'सड़कों और पुलों' में तेज वृद्धि को दिया जा सकता है। हालांकि, कई उद्योगों में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज होने के कारण 2020-21 में कुल परियोजना लागत में 2019-20 की तुलना में कमी आयी। उदाहरण के लिए, 'बिजली क्षेत्र' में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत

चार्ट 5: बैंकों/ एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी

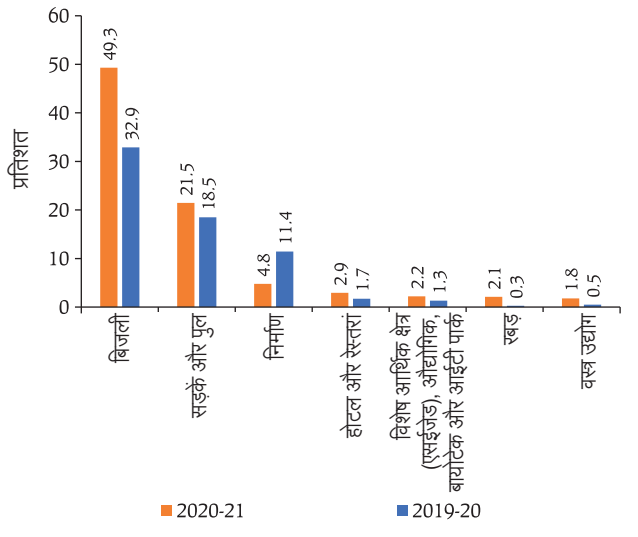

2019-20 में ₹57,855 करोड़ से घटकर ₹37,253 करोड़ हो गई, हालांकि 2020-21 में इसकी सापेक्ष हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसी तरह 'सड़कों और पुलों' के मामले में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत भी 2019-20 में ₹32,522 करोड़ से घटकर ₹16,224 करोड़ हो गई। यह स्मरण किया जा सकता है कि समग्र तौर पर, परियोजनाओं की कुल लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में आधे से अधिक (57 प्रतिशत) की गिरावट आयी है (चार्ट 5 और अनुबंध: सारणी ए7)।

चूंकि देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की अगुवाई में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की महती भूमिका है, इसलिए इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है और आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करने हेतु समय-समय पर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की गई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) ने 2020-25 की अवधि के दौरान ₹111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के साथ पांच साल का रोडमैप निर्धारित किया है, जिसमें परियोजनाओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा।

महामारी के कारण समग्र रूप से कमजोर निवेश माहौल के बावजूद उद्योग विवरण, स्वीकृत परियोजनाओं में परिलक्षित जानकारी की पुष्टि करते हैं। आगे बढ़ते हुए, इन नई इन्फ्रास्ट्रक्चर

परियोजनाओं (सड़कों और पुलों और निर्माण) के सफल कार्यान्वयन में वृद्धि बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि, महामारी ने अल्पावधि में इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की होगी, जो अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे गति पकड़ने के साथ कम होनी चाहिए।

(डी) राज्य-वार

एक परियोजना का स्थान चुनने के निर्णायक कारक निम्न हैं: कच्चे माल तक पहुंच, श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, बाजार का आकार और वृद्धि की संभावनाएं। पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के आंकड़ों से पता चला है कि आधे से अधिक (52.3 प्रतिशत) परियोजनाएं का आरंभ पांच राज्यों में शुरू किया गया था, *अर्थात* गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 2020-21 में इसके हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद, 2016-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान 2011-16 की पंचवर्षीय अवधि की तुलना में एक से अधिक राज्यों में परियोजनाओं के प्रसार में वृद्धि हुई है (चार्ट 6 और चार्ट 7)।

2020-21 में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान और गुजरात की सबसे अधिक (17.1 प्रतिशत) हिस्सेदारी थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश (15 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (13.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.5 प्रतिशत), हरियाणा (7.8 प्रतिशत), कर्नाटक (6.1 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण लाभ (10 से अधिक प्रतिशत अंक) दर्ज करने के साथ पंचवर्षीय अवधि के दौरान भी बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने हिस्से में गिरावट दर्ज की (चार्ट 8 और अनुबंध: सारणी ए8)।

चार्ट 7: 2011-12 से 2015-16* तक की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*

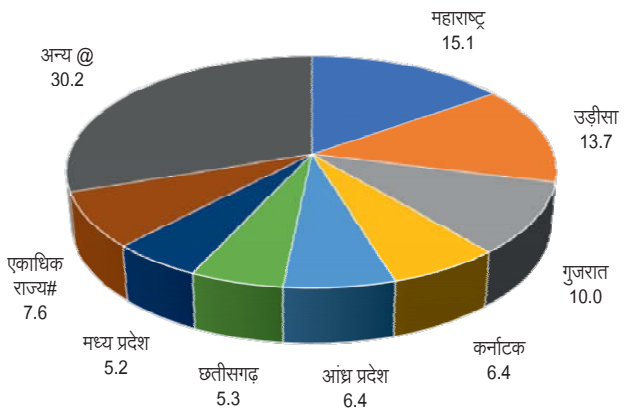

#: 'एकाधिक राज्यों' में चल रही परियोजनाएं
*: प्रतिशत में हिस्सेदारी
@: इसमें वे राज्य शामिल हैं जिनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत या उससे कम है।

चार्ट 6: 2016-17 से 2020-21* तक की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*

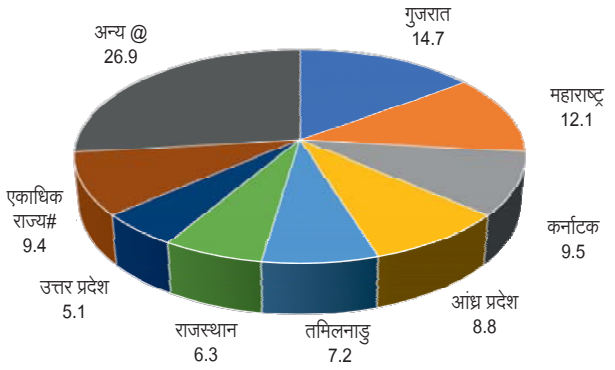

#: 'एकाधिक राज्यों' में चल रही परियोजनाएं
*: प्रतिशत में हिस्सेदारी
@: इसमें वे राज्य शामिल हैं जिनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत या उससे कम है।

चार्ट 8: बैंकों/ एफ़आई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी

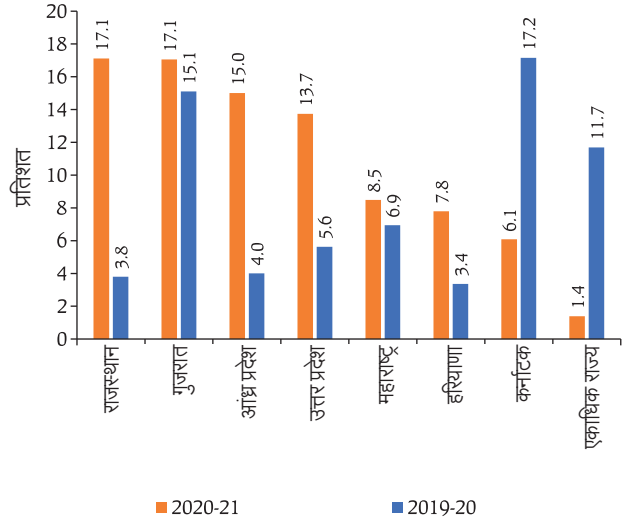

एकाधिक राज्य: एक से अधिक राज्यों में चल रही परियोजनाएं

IV. निवेश के प्रयोजन की चरणबद्ध रूपरेखा

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा की जानकारी से पूंजीगत व्यय का अल्पकालिक (एक वर्ष आगे का) पूर्वानुमान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 2020-21 में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध तरीके से संकेत मिलता है कि 2020-21 में कुल प्रस्तावित व्यय का 38.4 प्रतिशत (₹29,013 करोड़), 2021-22 में 34.6 प्रतिशत (₹26,166 करोड़) और 2021-22 के बाद के वर्षों में 18.8 प्रतिशत (₹14,179 करोड़) निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उपगत किया गया होगा। 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 8.2 प्रतिशत 2020-21 से पहले ही खर्च कर दिया गया था। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 2020-21 में नियोजित व्यय से परिकल्पित पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत (₹1,38,288 करोड़ से ₹1,23,240 करोड़) की गिरावट देखी गई (अनुबंध: सारणी ए1)।

अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में भी लगभग 59 प्रतिशत की कमी आई, जो लगातार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक रहा। पूंजी बाजार (इक्विटी माध्यम) ने 2020-21 में ₹159 करोड़ के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को समर्थित किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम था (अनुबंध: सारणी ए2, ए3)।

संक्षेप में, यह आंकलन किया गया है कि 2020-21 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा ₹1,60,407 करोड़ का कुल पूंजीगत व्यय (सभी माध्यमों से) किया जाएगा, जो कि नियोजित चरणबद्धता से 30 प्रतिशत की कम होगा। पिछला साल। इस तीव्र गिरावट का कारण वित्तपोषण के सभी माध्यम हैं (अनुबंध: सारणी ए4)।

पिछले वर्षों में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से स्वीकृत प्रक्रियाधीन परियोजनाओं [7] पर आधारित परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा यह दर्शाती है कि यह 2020-21 में ₹94,227 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹68,469 करोड़ होने का संकेत देती है। यह वित्तपोषण के सभी माध्यमों पर ध्यान में रखते हुए भी 2021-22 में ₹1,07,535 करोड़ (2020-21 में ₹1,13,171 करोड़) पर भी कम है। हालाँकि, यह बहुत संभव है कि 2020-21 के दौरान इनमें से कई की प्राप्ति नहीं की गई हो और 2021-22 में कुछ अन्य को आकस्मिक महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण प्राप्त नहीं जा सके (अनुबंध: सारणी ए1 और ए4)।

V. निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट निवेश

हाल के वर्षों में, कॉर्पोरेट क्षेत्र ने पूंजीगत व्यय वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में बॉन्ड और ऋण-पत्र (डिबेंचर) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जैसे कर्ज लिखतों पर आश्रित हुआ है। कर्ज के निजी स्थानन के आंकड़ों से पता चलता है कि 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कर्ज (बॉन्ड और डिबेंचर) के निजी स्थानन के माध्यम से निधि जुटाना काफी हद तक बढ़ा, लेकिन इसके बाद 2016-17 में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के बाद इसमें काफी कमी आयी। 2019-20 में गिरावट के बाद 2020-21 में इसमें इजाफा हुआ। पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एफडीआई की प्राथमिकता भी देखी गई है, जिसमें 2017-18 को छोड़कर 2012-13 से लगातार एफडीआई राशि में वृद्धि हुई है। तदनुसार, एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2020-21 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा (सारणी 1)।

सारणी 1: निजी स्थानन और एफडीआई

(₹ करोड़ में)

अवधि	कर्ज-निजी स्थानन*	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**
2011-12	27,040	165,146
2012-13	59,188	121,907
2013-14	56,042	147,518
2014-15	97,358	181,682
2015-16	118,317	262,322
2016-17	153,356	291,696
2017-18	136,599	288,889
2018-19#	129,971	309,867
2019-20#	105,699	353,558
2020-21#	128,930	442,569

*: केवल निजी क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए

**: आवक एफडीआई में केवल इक्विटी पूंजी शामिल है

#: अनंतिम आंकड़े

स्रोत: प्राइम डेटाबेस और भारत सरकार

[7] प्रक्रियाधीन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन पहले ही आरंभ चुका है। किसी प्रक्रियाधीन परियोजना से पूंजीगत व्यय किसी वर्ष के लिए वे परिकल्पित राशियां हैं, जो उस वर्ष से पहले वाले वर्ष में मंजूर हो चुकी हैं।

VI. निष्कर्ष

यह आलेख समग्र निवेश प्रयोजन पर पहुंचने और निकट अवधि में निवेश गतिविधि के दृष्टिकोण का आंकलन करने के लिए अपने परियोजना प्रस्तावों की चरणबद्ध योजनाओं (*प्रत्याशित*) के आधार पर निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश के प्रयोजन पर डेटा का उपयोग करता है।

कोविड-19 से पहले भी अर्थव्यवस्था मंद निवेश की भावना से सराबोर थी, जैसा कि कम संख्या में परियोजनाओं की नई घोषणाओं के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं के जीवन चक्र के विस्तार से परिलक्षित होता है। महामारी ने 2020-21 के दौरान नई परियोजनाओं की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और प्रक्रियाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी बाधा उत्पन्न की। प्रक्रियाधीन परियोजनाओं से संबंधित समय-सीमा की निगरानी करना - इसके विस्तार की सीमा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से संभावित परिणाम की रेंज (पूर्णता/ परित्याग/ आस्थगन आदि) - इसलिए महत्वपूर्ण होगी। परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा 2021-22 में निजी निवेश दृष्टिकोण के लिए निकट-अवधि के जोखिमों को दर्शाता है, जबकि 2021-22 में नई परियोजनाएं निजी निवेश के दृष्टिकोण को आकार देंगी; प्रक्रियाधीन परियोजनाएं 2020-21 से 2021-22 तक आस्थगित प्रक्रियाधीन निवेश से सामान्य को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे निजी निवेश पर समग्र जोर सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है।

अनुबंध

सारणी ए1: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

मंजूरी देने का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरी के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़)	संशोधन/ निरसन* के कारण परियोजना लागत & (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011-12 तक				2,90,613	1,78,643	86,858	21,408	3,044	869						
2012-13	414	1,96,345	1,89,483 (3.5)	36,664	56,725	48,976	27,325	11,219	6,447	2,045					
2013-14	472	1,34,019	1,27,328 (5.0)	1,332	15,139	34,769	44,925	19,909	7,105	2,677	1,472				
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)		98	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036			
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)			3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220		
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)			1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086	
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)				620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)					569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,698
2019-20	320	2,00,038	1,75,830 (12.1)							4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	16,607
2020-21	220	75,558									2,491	3,709	29,013	26,166	14,179
कुल#				**3,28,609**	**2,50,605**	**1,90,564**	**1,40,253**	**1,38,595**	**1,43,077**	**1,33,172**	**1,46,665**	**1,38,288**	**1,23,240**	**68,469**	**33,726**
प्रतिशत परिवर्तन					**-23.7**	**-24.0**	**-26.4**	**-1.2**	**3.2**	**-6.9**	**10.1**	**-5.7**	**-10.9**	*****	

: कॉलम के योग किसी वर्ष विशेष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिनमें केवल परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

*: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2021-22 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधन/ निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी** के माध्यम से वित्तपोषित कैपेक्स परियोजनाओं* की चरणबद्धता

मंजूरी देने का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			38,342	15,673	2,400	100								
2012-13	519	65,692		37,792	20,267	6,300	1,333							
2013-14	563	80,736			56,197	20,976	3,563							
2014-15	478	57,327				36,791	16,806	3,151	575	2	2			
2015-16	314	38,885					28,998	7,311	2,572	4				
2016-17	346	22,154						14,953	6,005	1,192	2	2		
2017-18	419	37,896							17,822	13,054	6,484	529	7	
2018-19	515	72,490								46,221	17,725	1,236	5,398	1,910
2019-20	495	95,491									65,367	17,157	11,717	1,250
2020-21	344	40,382										18,084	21,523	775
कुल&			**38,342**	**53,465**	**78,864**	**64,167**	**50,700**	**25,415**	**26,974**	**60,473**	**89,580**	**37,008**	**38,645**	**3,935**
प्रतिशत परिवर्तन				**39.4**	**47.5**	**-18.6**	**-21.0**	**-49.9**	**6.1**	**124.2**	**48.1**	**-58.7**	**#**	

*: जिन परियोजनाओं को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

**: रुपये में अंकित बांड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए हैं।

#: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की है क्योंकि 2021-22 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों* के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

इक्विटी निर्गम की अवधि ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित कैपेक्स (₹ करोड़ में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			1,186	455										
2012-13	25	1,135		533	494	108								
2013-14	21	454				384	70							
2014-15	24	1,078				189	557	332						
2015-16	40	4,511				11	644	2,753	849	183	71			
2016-17	29	1,159					14	471	368	163	143			
2017-18	51	1,538							419	327	787	5		
2018-19	39	609								506	90	13		
2019-20	12	53								2	49	2		
2020-21	12	663										139	421	103
कुल&			**1,186**	**988**	**494**	**692**	**1,285**	**3,556**	**1,636**	**1,181**	**1,140**	**159**	**421**	**103**
प्रतिशत परिवर्तन				**-16.7**	**-50.0**	**40.1**	**85.7**	**176.7**	**-54.0**	**-27.8**	**-3.5**	**-86.1**	**#**	

*: जिन परियोजनाओं को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

#: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2021-22 में लागू होने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ आईपीओ/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी*/ आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

कंपनियों की संख्या ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	बैंक/ वित्तीय संस्था/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी/ आईपीओ													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			3,30,141	1,94,771	89,258	21,508	3,044	869						
2012-13	958	2,56,310	36,664	95,050	69,737	33,733	12,552	6,447	2,045					
2013-14	1,056	2,08,518	1,332	15,139	90,966	66,285	23,542	7,105	2,677	1,472				
2014-15	828	1,45,658		98	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038			
2015-16	700	1,35,177			3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220		
2016-17	916	2,02,562			1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	4,003	2,086	
2017-18	955	2,07,673				620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	10,736	2,349	242
2018-19	963	2,32,288					569	6,862	11,000	1,06,700	64,895	22,497	15,157	4,608
2019-20	827	2,71,374							4,049	14,526	1,19,394	75,715	39,833	17,857
2020-21	576	1,16,603								2,491	3,709	47,236	48,110	15,057
कुल&			**3,68,137**	**3,05,058**	**2,69,922**	**2,05,112**	**1,90,580**	**1,72,048**	**1,61,782**	**2,08,319**	**2,29,008**	**1,60,407**	**1,07,535**	**37,764**
प्रतिशत परिवर्तन				**-17.1**	**-11.5**	**-24.0**	**-7.1**	**-9.7**	**-6.0**	**28.8**	**9.9**	**-30.0**	#	

*: रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए हैं।

#: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2021-22 तक स्वीकृति की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

&: आकलन प्रत्याशित हैं, जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए5: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

अवधि		₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ तक	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ तक	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2011-12	परियोजनाओं की संख्या	420	145	36	26	9	**636**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.3	17.0	13.7	27.6	33.4	**100 (1,91,592)**
2012-13	परियोजनाओं की संख्या	245	119	20	23	7	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	4.8	14.6	7.3	26.8	46.4	**100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	214	76	34	21	1	**346**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.6	20.9	26.0	38.5	5.9	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	287	180	29	40	5	**541**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	5.8	23.3	11.9	41.7	17.4	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	263	149	28	42	3	**485**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	5.2	21.0	10.8	43.8	19.1	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	220	110	39	36	4	**409**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	4.8	17.0	17.0	39.6	21.6	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	150	84	45	36	5	**320**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	3.3	11.9	18.6	37.4	28.8	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	128	52	15	24	1	**220**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	5.5	16.8	14.2	53.5	10.0	**100 (75,558)**

टिप्पणी : i. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत को दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

सारणी ए6: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	नई	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल
2011-12	परियोजनाओं की संख्या	449	172	5	10	**636**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	70.6	23.1	0.1	6.3	**100 (1,91,592)**
2012-13	परियोजनाओं की संख्या	303	107	-	4	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	84.2	14.7	-	1.1	**100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	65.2	20.1	-	14.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	39.4	14.7	0.2	45.7	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	260	64	3	19	**346**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	73.6	14.3	0.1	12.0	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	429	97	4	11	**541**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	78.6	9.9	0.1	11.3	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	396	80	2	7	**485**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	89.0	9.5	0.1	1.5	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	309	80	-	20	**409**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	76.8	19.3	-	3.9	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	262	37	1	20	**320**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	79.8	13.7	-	6.4	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	181	38	1	-	**220**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	94.1	5.9	-	-	**100 (75,558)**

टिप्पणी: i. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत को दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

iii.-: शून्य/ नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

उद्योग	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
इन्फ्रास्ट्रक्चर	107	47.4	82	47.9	87	39.8	74	48.8	108	72.0	204	62.6	150	51.8	122	60.4	99	61.5	63	74.3
i) बिजली	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3
ii) दूरसंचार	1	0.0	2	5.6	1	0.0	1	4.9	1	0.3	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2
vi) सड़कें और पुल	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5
निर्माण	23	1.8	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8
होटल और रेस्तरां	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	26	1.9	16	1.7	4	2.9
रबड़ उत्पाद	18	0.9	7	0.5	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	5	0.5	5	0.3	17	2.1
वस्त्र	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8
रसायन और उर्वरक	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6
खाद्य पदार्थ	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5
सीमेंट	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3
धातु और धातु के उत्पाद	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8
फार्मास्युटिकल्स	20	0.8	10	0.4	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	9	0.3	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	0.0	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3
परिवहन उपकरण	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.8	5	0.4	2	0.3
खनन और उत्खनन	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	0.0	7	5.6	6	5.3	2	0.2
अन्य*	144	11.0	80	5.8	102	14.1	65	7.5	61	7.4	77	3.9	65	6.7	80	8.5	53	13.4	36	7.7
कुल	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	**1,91,592**		**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**	

*: कृषि और संबंधित गतिविधियों, कागज और कागज से बने उत्पाद, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़ के उत्पाद, आईटी सॉफ्टवेयर, संचार, व्यापार सेवाएं, कागज और कागज उत्पाद, मनोरंजन, अन्य विनिर्माण, अन्य सेवाओं आदि जैसे उद्योगों शामिल हैं।

- : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
राजस्थान	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1
गुजरात	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1
आंध्र प्रदेश	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0
उत्तर प्रदेश	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.6	30	13.7
महाराष्ट्र	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5
हरियाणा	45	1.4	18	1.2	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8
कर्नाटक	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1
असम	3	0.2	1	0.5	4	0.3	2	0.2	4	0.4	10	0.6	5	0.8	4	0.2	1	0.3	3	4.4
मध्य प्रदेश	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	7.0	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9
छत्तीसगढ़	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2
तमिलनाडु	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7
पंजाब	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7
पुदुचेरी	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.5
पश्चिम बंगाल	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4
झारखंड	12	1.3	8	1.2	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	0.0	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2
जम्मू और कश्मीर	5	0.2	10	0.2	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	11	0.4	3	0.1	5	0.2
हिमाचल प्रदेश	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2
एकाधिक राज्य#	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4
अन्य*	46	14.0	41	34.1	32	12.5	23	17.3	25	4.6	38	7.5	32	9.0	46	8.2	26	7.1	8	0.2
कुल	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	**1,91,592**		**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**	

#: इसमें एकाधिक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

*: इसमें शेष राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

'-': शून्य/ नगण्य अथवा सूचना उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।